# Repayment of Public Debt

जिसप्रकार एक व्यक्ति अथवा संगठन को लिया हुआ ऋण लौटाना पड़ता है ठीक उसीप्रकार सरकार को भी न केवल सरकारी ऋण का ब्याज अपितु मूलधन भी अदा करना पड़ता है। क्यों कि सरकारी ऋण केवल जनता पर करों का बोझ नहीं डालते बल्कि लोगों पर अनैतिक प्रभाव भी डालते हैं। अतः जितनी जल्दी ऋण अदा हो जाए उतना ही सरकार के लिए अच्छा होता है।

यदि सरकारी ऋणों का उपयोग उत्पादक कार्यों के लिए किया जाता तो इसका भुगतान करना तत्काल जरूरी नहीं होता क्योंकि इस स्थिति में सरकार को ऋण का ब्याज अदा करने के लिए आय का एक स्त्रोत मिल जाता होता है।

यदि सरकार ऋण का अधिकांश भाग अनुत्पादक कार्यों पर खर्च होता है तो जितनी जल्दी इसे अदा कर दिया जाए जनता के हित में उतना ही अच्छा होता है।

सरकार अपने ऋण का परिहार करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाती है —

## 1 ऋण नकार (Repudiation of Public Debt)

ऋण नकार का अर्थ है कि सरकार अपने दायित्वों को स्वीकार नहीं करती और ब्याज अथवा मूलधन दोनों ही के भुगतान से इंकार करती है। इन्कारी का अर्थ है ऋण को स्थगित करना ही नहीं बल्कि उसे नष्ट करना भी है। रूस की सोवियत सरकार तथा 1861-65 के गृहयुद्ध के पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका ने नागरिकों से लिए गए ऋणों की वापसी से इन्कार कर दिया था। लेकिन सामान्यतः एक सरकार अपने

ऋणों की अदायगी से इंकार नहीं करती क्योंकि ऐसा करने से सरकार में सामान्य जनता का विश्वास समाप्त हो जाता है। फिर भी चरम परिस्थितियों में, कोई भी सरकार अपने आन्तरिक एवं बाह्य ऋण दायित्व से इंकार करने को बाध्य हो सकती है।

## 2. ऋण रूपान्तर (Conversion of Debt)

ऋण शोधन का एक अन्य तरीका ऋण की बदली का है। इसके अन्तर्गत एक पुराना ऋण नए ऋण में निर्गमित किया जाता है। हो सकता है कि जब सरकार ने ऋण लिया हो तो ब्याज की दर बहुत ऊंची हो। किन्तु जब ब्याज दर गिरी हुई होती है तो सरकार पुराने ऋणों को कम ब्याज वाले नये ऋणों में बदल देती है। ताकि राज्यों पर ऋण का भार न्यूनतम हो सके। इस क्रिया से ऋण का स्वरूप बदल जाता है।

किन्तु ऋणों की बदली का कार्य तभी होता है जब सरकार की साख अच्छी हो और उसके पास सामान्य से अधिक स्टॉक हो। डाल्टन ने ऋण रूपान्तर विधि की आलोचना करते हुए कहा है कि "यद्यपि इस विधि में वर्तमान ऋण-भार कम हो जाता है तथापि भावी ऋण-भार बढ़ जाता है। क्योंकि बाजारों में ऋणपत्रों के मुल्यों में वृद्धि हो जाती है। बाजार में ब्याज दर कम होने पर राज्य का ऋण-भार और अधिक हो जाता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति राजकीय पत्रों में विनियोग करना चाहता है।" इसलिए ऋण रूपान्तर की विधि को अपनाते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना होता है —

(1) मुद्रा की मांग तथा उनकी पूर्ति सुचारु रूप से हो

(ii) भविष्य में परिवर्तित होने वाले मूल्यों, कर, ब्याज की दरों का भी पूर्ण रूप से जानकारी हो।
(iii) आवश्यकता पड़ने पर ही नये ऋणों के मूल्यमान में वृद्धि की जाए।

## 3. क्रमानुसार बॉण्ड भुगतान (Serial Bond Redemption)

सरकार यह निश्चय कर सकती है कि वह पहले जारी किए गए बॉण्डों का कुछ भाग प्रतिवर्ष अदा करती रहे। अतः ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि सरकारी ऋण का कुछ भाग प्रतिवर्ष परिपक्व हो जाया करे। इन बॉण्डों की क्रम संख्या के बारे में भी प्रारम्भ में ही निर्णय किया जा सकता है जो कि प्रतिवर्ष परिपक्व होगा। इस पद्धति से ऋण का निश्चित भाग प्रतिवर्ष अदा कर दिया जाता है। इसप्रकार के ऋण शोधन की एक किस्म यह भी है कि प्रतिवर्ष परिपक्व होने वाले बॉण्डों की क्रम संख्या का निर्णय लॉटरी द्वारा निर्धारित कर लिया जाए। अमेरिका की स्थानीय निकाय इस विधि का प्रयोग करती है।

## 4. ऋण परिशोधन कोष (Sinking Fund)

ऋण परिशोधन कोष को सबसे पहले इंग्लैण्ड ने अपनाया। उसके बाद विश्व के अन्य राष्ट्रों ने इसे अपनाया। शोधन निधि का अर्थ है एक ऐसी निधि का निर्माण जिसमें कि सरकारी आय का एक निश्चित भाग प्रतिवर्ष जमा किया जाता है और उस निधि से ऋणों का भुगतान किया जाता है। पहले शोधन निधि में धन का संचय उस समय तक होता रहता था जबतक कि ऋणों की अवधि पूर्ण न हो जाए। परन्तु आजकल इन निधियों से जैसे ही धन उपलब्ध

होता है तुरन्त ही ऋणों का निपटारा करने में उपयोग कर लिया जाता है। शोधन निधि और प्रकार की होती है। इसका सबसे अधिक प्रचलित रूप निम्न है

मानलीजिए कि सरकार ने सड़क निर्माण के लिए Rs 10 करोड़ का ऋण लिया है जिसका निपटारा 10 वर्षों में होना है। सरकार ऋण लेने के समय से ही पेट्रोल पर कर लगा सकती है और उसकी प्राप्तियों को एक निधि में जमा कर सकती है यह निधि ही शोधन निधि कहलाती है। प्रतिवर्ष करों की प्राप्तियाँ तथा विनियोग से प्राप्त होने वाला ब्याज इस निधि में जुड़ता रहता है और इसप्रकार 10 वर्षों के पश्चात् यह उधार ली गई मूल धन राशि के बराबर हो जाती है और तब उस समय इससे ऋण की अदायगी कर दी जाती है।

लेकिन शोधन निधि के इस्तेमाल का एक खतरा यह है कि सरकार आवश्यकता के समय सम्भव है इतना धैर्य न रख सके कि ऋण की परिपक्व तिथि तक का इन्तजार करे और उसका उपयोग इस कार्य के अलावा जिसके लिए कि मूलत: शोधन निधि का निर्माण किया गया था, अन्य किसी कार्य के लिए कर ले।

इसलिए आजकल इन निधियों से जैसे ही धन उपलब्ध होता है तुरन्त ही ऋणों का निपटारा करने में उनका उपयोग कर लिया जाता है। अथवा इनका उपयोग या तो उन बॉण्डों को अदा करने में किया जाता है जो प्रतिवर्ष परिपक्व होते हैं या उनका उपयोग बाजार के ~~बॉण्ड~~ बॉण्ड्स को खरीदने में कर लिया जाता है।

## 5. अनावर्ती पूँजी कर (Capital Levy)

सरकार ऋण का निपटारा अनावर्तित पूंजी कर,

Scanned with CamScanner

लगाकर भी किया जा सकता है। यह कर सरकार द्वारा आय प्राप्त करने के लिए केवल एकबार लगाया जा सकता है इसकी आमतौर पर युद्ध के एकदम बाद लगाने की वकालत की जाती है ताकि युद्धकालीन अनुत्पादक ऋणों का भुगतान किया जा सके।

अनावर्त्त पूंजी के सम्बन्ध में अनेक तर्क वितर्क प्रस्तुत किए गए है -

## पक्ष में तर्क

(a) युद्धकालीन ऋण जहाँ अनुत्पादक होता है वहाँ समाज के लिए फलहीन भी होता है। अतः कोई विशिष्ट कर अथवा अनावर्त्ती पूंजी कर लगाकर उस ऋण को एक बार में ही चुका देना अच्छा होता है।

(b) अनावर्त्ती पूंजी कर को इस आधार पर भी न्यायोचित ठहराया जाता है कि जिन लोगों ने युद्ध काल में भारी मुनाफे कमाए है उन्हें बिना किसी कष्ट के ऋणों का निपटारा करने में अपना अंशदान देना चाहिए।

(c) अनावर्त्ती पूंजी कर का प्रभाव मुद्रास्फीती विरोधी होता है क्योंकि यह धनी लोगों के हाथों में से फालतू क्रयशक्ति ले लेता है।

(d) अनावर्त्ती पूंजी कर द्वारा सरकारी ऋण का शोधन करने वाले उच्च आय वाले वर्ग के लोग उसी पूर्व स्थिति में बने रहते है क्योंकि वे अनावर्त्ती पूंजी के रूप में सरकार को जो कुछ देते है वे ऋण वापसी के रूप में सरकार से प्राप्त कर लेते है।

(e) युद्ध काल में, समाज में आय तथा धन का भी असमान वितरण होता है अनावर्त्ती पूंजी कर उसे घटाने में सहायक होता है। अतः यह आय एवं धन के वितरण को समान बनाता है।

(f) अनावर्त्ती पूंजी कर के द्वारा लोकऋणों को एकदम

वापिस करने से लोगों को भविष्य में करों की अदायगी के लिए लगने वाले कर का डर खत्म हो जाता है।

## विपक्ष में तर्क

इन सबके बावजूद अनावर्ती पूंजी कर के विरोध में निम्न बातें प्रस्तुत की गई है —

(a) अनावर्ती पूंजी कर विदेशी में अन्तप्रवाह (inflow) में कमी उत्पन्न करता है जिसका दीर्घकाल में उद्योग व वाणिज्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(b) अनावर्ती पूंजी कर उन्हीं पर लगाया जाता है जो धनी संख्या अमीर बनते है। इससे कर वंचन (tax evasion) को बढ़ावा मिल सकता है।

(c) इससे लोगों के काम करने, बचत करने तथा निवेश करने की इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

इन पक्ष विपक्ष के तर्कों के बावजूद अनावर्ती पूंजी कर सामान्य विशेष पर आवश्यक होता है। परन्तु capital levy में यह खतरा बना रहता है कि सरकार कहीं बार बार इसका आश्रय लेने को उत्सुक न हो जाए।

## 6. विदेशी ऋण की वापिसी (Repayment of External debt)

विदेशी ऋण का शोधन केवल अनुकूल भुगतान संतुलन के द्वारा सम्भव है जिसके ऋण चुकाने के लिए आवश्यक विदेशी विनिमय का संचय कर लिया जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ती के लिए यह आवश्यक है कि विदेशी ऋणों का विनियोग बड़ी सावधानी से ऐसे उद्योगों में किया जाय जिनमें कि उत्पादन की भारी सम्भावनाएँ मौजूद हो और प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्यात में वृद्धि करे। इसके साथ ही निर्यात बचतों (export surplus) को वस्तुओं के रूप में रखना चाहिए जो कि तत्काल विदेशियों द्वारा खरीद

Scanned with CamScanner

ली जाती है। इसके अलावा निर्यात विशिओं के लिए घरेलू उपभोग में कटौती कर ली जाए।

उपर्युक्त रीतियों के द्वारा सरकारी ऋण का भुगतान किया जा सकता है किन्तु ऋण नकार की रीति नहीं अपनानी जाए तो ठीक है। सबसे प्रचलित एवं उपयुक्त रीति यही है कि सरकारी ऋण का कुछ भाग प्रतिवर्ष निपटा दिया जाए।

—x—

Dr Sandhya Rani
Dept of Economics
Maharaja College

Scanned with CamScanner